



VISION IAS
04 AUG 2023
RECEIVED

VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
10-1 PM
04 AUG 2023
No. 3
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2419)

Name of Candidate	VIPIN DUBEY		
Medium Eng./Hindi	HINDI	Registration Number	584126
Center	DELHI (M NAGAR)	Date	04/08/2023

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

- Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
- There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH** इसमें बीस प्रश्न हैं हिन्दी और अंग्रेजी में छपे हैं।
- All questions are compulsory.**
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
- Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar
Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Discuss the role played by the Directorate of Enforcement in the investigation of offence of money laundering and violations of foreign exchange laws. (Answer in 150 words) 10

मनी लॉन्ड्रिंग से सावपाय कवैध एवं अवैध गतिविधियों से कर्जित धन को वैध बनाने की प्रक्रिया है। इसी जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय एवं विनीय कायूचना इकाई हैं।

प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका

- ① जांच करना - यह कवैध सम्पत्तियों की जांच करता है।
→ FCRA और FEMA के तहत विदेशी मुद्रा कानूनों की जांच।

② अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

→ अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग पर सहयोग।

→ कायूचना तंत्र को मजबूत करना।

③ निर्वाह करना

→ कवैध रूप से कर्जित सम्पत्तियों को जबरन करना।

→ संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करना।

- ④ नेटवर्क की जांच संगठित दलाली एवं
हाथकवादी वित्त पोषण के तहत सहयोग को रोकना।

पुनर्निर्माण

- ① प्रभावी रोक नहीं - विजय गारुमा, नील मोदी
मुहल चोकली आदि पर प्रभावी कार्रवाई
नहीं हो पायी है।

- ② स्विस बैंक

वर्तमान में भी भारतीयों के धन स्विस
बैंक में जमा है → धन वापसी नहीं हुई है।
→ जमाखोरी भी जारी है।

- ③ ED का राजनीतिकरण

राजनीतिक हित के लिए ED का दुरुपयोग

बागें की तरह → ED की दृष्टिकोण से नजरबंदी
→ बंतराखीप एजेंसी के साथ
सूचना सहयोग में बहि
पर्याप्त बजरीप हावरन

कतः ED के प्रभावी स्वरूप से
अव्यचार पर रोक लगायी जा सकती है।

2. भारतीय संविधान भारत में उदार लोकतंत्र के विकास हेतु एक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है।
विश्लेषण कीजिए।

The Indian Constitution has been successful in providing a framework for liberal democracy to flourish in India. Analyse. (Answer in 150 words) 10

भारतीय संविधान ने संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया है जिसने लोकतंत्र की मूल भावना जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन निहित है।

भारतीय संविधान यह ढांचा प्रदान करने में सफल भी रहा है जैसे

① 73वें एवं 74वां संविधान संशोधन

- 1) लोकतांत्रिक विभेदीकरण एवं आध्यात्मिक स्वतंत्रता लोकतंत्र को संकल्पना सफल करी है।
- 2) राजनैतिक एवं प्रशासनिक लोकतंत्र सुनिश्चित हुआ है।

② शक्ति प्रचलन

- 1) विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में शक्तियों का बँटवारा है।
विधायिका
कार्यपालिका न्यायपालिका
- 2) कार्यपालिका विशेषज्ञता स्थापित करी है।

③ शक्तियों का विभाजन

- 1) केंद्र व राज्यों के बीच (अनुच्छेद-7)
- 2) राज्य व पंचायतों के बीच (अनुच्छेद-11 एवं 14)

④ निर्वाचन की प्रक्रिया

- 1) संसद के सदस्यों के निर्वाचन में जनता की भागीदारी।
- 2) निर्मुक्ता पट रोक

⑤ स्वतंत्र एवं निस्पृह संवैधानिक बोधो

- 1) CAG के द्वारा लोक विन का संरक्षण अनुच्छेद (148)
- 2) UPSC के द्वारा शक्तिशाली भारतीय सेवकों का चयन।
- 3) विन बोधो द्वारा राजकीय संघर्ष की भण्डारी।

⑥ लिखित एवं सर्वोच्च संविधान

1) संविधान की संरचना है

बोधो की
राह

→ सामाजिक एवं धुंधी बोधो की
सिफारिशों का लागू करना

→ संविधान की सर्वोच्चता बनाए
रखना

→ राजावादा बुरा वाद के बुरा रूप
शक्ति प्रदर्शन का पालन

अतः संविधान में निहित शक्तों के
बुरा रूप उदात्त लोकतंत्र को सामाजिक,
आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के लिए आवश्यक
बनाया जा सकता है।

3. "समनुषंगिता के सिद्धांत" से आप क्या समझते हैं? भारत के संदर्भ में इसके महत्व की विवेचना कीजिए।

What do you understand by the "principle of subsidiarity"? Discuss its importance in the context of India. (Answer in 150 words) 10

समनुषंगिता के सिद्धांत से आशय
तत्काल व्यवहार करने से है।

आशय से महत्व

1) शासन की विविधता को प्रोत्साहित
करना।

2) स्थितिगतता को ध्यान में रखा।

3) मौखिक कर्तव्यों का पालन करना।

4) DRSP के सिद्धांतों के अनुसरण।

5) नागरिक क्रेडिट शासन, नागरिकों
का प्रशासनिक प्रतिक्रिया करना।

6) जीवनशैली को गंभीर बनाना।

7) विवेकीकरण की भावना को प्रोत्साहित।

8) विविधता के कर्तव्यों का पालन।

कृत्वा समुच्चयिका का सिद्धांत सर्वजन
हिताय सर्वजन दुष्काय पर आधारित है

4. "मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों का दमन करना नहीं होगा, बल्कि लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति उसी रूप में जागरूक बनाकर एक लोकतांत्रिक संतुलन स्थापित करना है, जिस प्रकार से वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं।" चर्चा कीजिए।

"The moral value of fundamental duties would not be to smother rights but to establish a democratic balance by making the people conscious of their duties equally as they are conscious of their rights". Discuss. (Answer in 150 words) 10

42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में
मूल कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद
51A में स्थान मिला जिससे नागरिक
होने कर्तव्यों के साथ-साथ कर्तव्यों से
भी ठकान रहे।

मूल कर्तव्यों का योगदान → लोकतांत्रिक संतुलन में

- * अनुच्छेद 51A(e)
↳ नागरिकों के बीच भावना को बढ़ावा, भाषाई एवं धार्मिक कटुता की रक्षा एवं स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग
↳ यह नैतिक कर्तव्य अनुच्छेद 29, 15 से भी संबंधित है।

- * अनुच्छेद 51A(f)
↳ इसका उद्देश्य गौरेवशाली सामंजसिक संस्कृति पंथ का संरक्षण है
↳ मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 29, 30 एवं 32 भी इसी की बात बताते हैं।

4) अनुच्छेद 51 A (4)

↳ हिंसा से दूर रहना

मौलिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकार

1) ये पासपर प्ररक हैं।

2) जो हमारे कर्तव्य हैं वे हमारे
अधिकार हैं।

↳ मैट्रो में महिलाओं एवं बच्चों
के लिए सीटों का संरक्षण।

3) ऐसे में मौलिक कर्तव्यों के लिए
जागरूकता अधिकारों के संरक्षण को
बढ़ावा देगा।

निष्कर्ष: कहा जा सकता है कि
मौलिक कर्तव्य एवं अधिकारों के संयोजन
से ही प्रथम स्वतंत्रता एवं सम्मान
संरक्षित हो सकती है।

5. क्या आपको लगता है कि कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजित विधान का प्रयोग शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है? भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Do you think the exercise of delegated legislation by the executive goes against the principle of separation of powers? Discuss in the context of India. (Answer in 150 words) 10

प्रत्यायोजित विधान से शासक शासन
द्वारा कानून निर्माण की प्रक्रिया कार्यपालिका
को सौंपने से है।

शासक प्रयत्न के सिद्धांत के विरुद्ध

⊗ तथ्यादेश

- 1) मधुसूदन 123 एवं 313 के तहत अल्पसंख्यक
विधायी कानून कार्यपालिका द्वारा निर्मित

↳ रूपट बनाम शासन संघ - न्यायालय ने
कहा कि इसमें जांच हो सकती है कि
तत्काल आवश्यकता की आवश्यकता थी या नहीं

- ↳ D.C. वायवाक्काग बिहार (1987) → तथ्यादेश
विधायिका का विरुद्ध नहीं हो सकता है

⊗ जनता के विपरीत

- 1) जनता ने विधायिका का चुनाव भीति
निर्माण एवं विधि निर्माण के लिए किया
है

*) विशेषज्ञता

- १) विद्यापिका के पास विशेषज्ञता होती है
- २) विधि निर्माण से पूर्व विभिन्न शोधोद्यम से संवाद।
- ३) संसद / विधानमण्डल द्वारा व्यापक चर्चा के बाद विधि निर्माण।

उत्पादोन्मुख विधान की प्रासंगिकता① विद्यापिका पर उद्यमिक दबाव

- १) सदन का सत्र न चलना
- २) सदन की उत्पादकता में कमी आती है

② पूरक कानून का निर्माण

- १) संसद का अधिकार है कि वह कार्यपालिका को पूरक कानून निर्माण अधिकार दे सकती है

निष्कर्ष: उत्पादोन्मुख विधान के द्वारा विधि निर्माण में तीव्रता आती है। ऐसे में कार्यपालिका को यह ध्यान देना होगा कि ऐसे विधान लेविद्यान एवं जनहित के अनुकूल हों।

6. दोषपूर्ण गवर्नेंस के पीछे प्रमुख कारण एक ढर्रे में सोचने की आदत और एकाकी कार्य प्रणाली है। भारत में लोक सेवाओं के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए।
A key factor behind poor governance is a system of thinking and working in silos. Discuss in the context of public services in India. (Answer in 150 words)

10

1950-1991 के मध्य भारत में विकास की धीमी गति का एक मुख्य कारण लोक सेवाओं में नवाचार का अभाव था जिससे वे विधि को स्वाधि करना पग उद्देश्य मानने लगे और भावनात्मक रूप से स्वाधिका

दोषपूर्ण गवर्नेंस के पीछे रहती प्रसंगिता

- ① सामाजिक, हार्थिक एवं राजनीतिक व्याप के लक्षकों
1) लोकसेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वविवेकाधिकार का प्रयोग व्याप स्वाधिका के लिए करें।
2) इससे स्वविवेकाधिकार → निर्दुशला → अस्वाचार → जानकीतावादी को बढ़ावा।

② नवाचार का अभाव

- 1) क्रिटिकल थिंकिंग में रुकी → नई समस्याओं का समाधान न कर पाना।
2) परंपरागत ढांचा के साथ कार्य करना
↳ IT को फोलाहन नहीं

③ लोकनिधि का दुरुपयोग

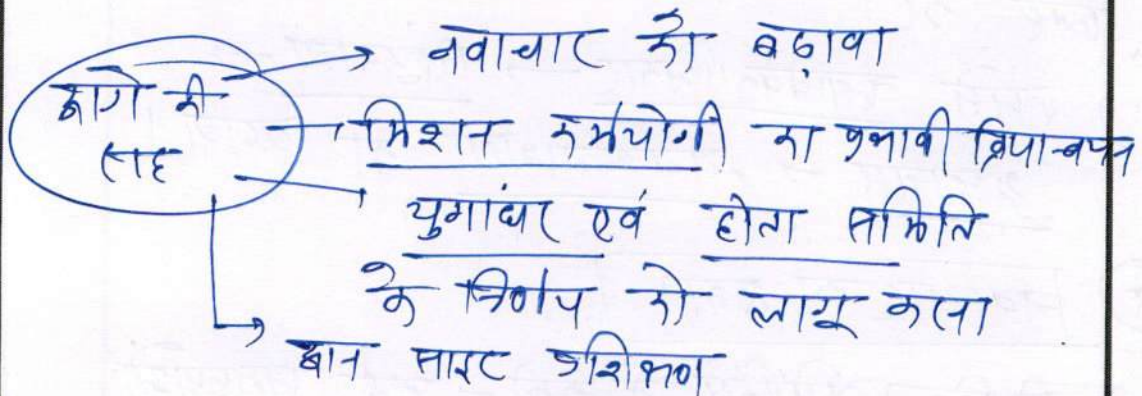
- 1) मालिक की श्रमिका में काम करना, स्वयं
को सेवक न समझना।
- 2) स्वहित को जनहित पर महत्व

④ RTI का उपयोग न करना

- 1) बस्तीहृति की दर 8.5% है।
- 2) इसका कारण यह है कि लोकसेवक जनता
को सूचना प्रकट नहीं करना चाहते हैं।

⑤ ई-गवर्नेंस के लिए नकारात्मक भावना

- 1) पारदर्शिता में इडि होने से अधिकारों में
रुकी।



कतः लोकसेवकों की नवाचारशीलता
ही लोकसेवा को जीवंत बना सकती है जिसे
मिना (नवरत्न IAS) की पहल 'Fund Your City'
एवं देवांश यादव (IAS) की 'crowd funding'

7. असुरक्षित गर्भपात भारत में महिलाओं के प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए उत्तरदायी कारणों की पहचान कीजिए और उपचारात्मक उपाय भी बताइए।

Unsafe abortions are a critical issue affecting the reproductive and maternal health of women in India. Identify the reasons behind the same and suggest remedial measures as well. (Answer in 150 words) 10

भारत में असुरक्षित गर्भपात से प्रत्येक दिन [8] महिला की मृत्यु हो जाती है। इसमें से अधिकांश 15-19 वर्ष की लड़कियाँ होती हैं।

उत्तरदायी कारण

① लैंगिक एवं जनन स्वास्थ्य

- 1) जागरूकता का अभाव।
- 2) सेफ मेमस प्रेसिडेस का अभाव।
- 3) यौन शिक्षा का अभाव।

② ASHA एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की निष्क्षिप्तता

- 1) प्राथमिक सहायता न मिल पाना।
- 2) इनके प्रशिक्षण का अभाव।

③ विशेषज्ञता

- 1) गर्भपात करने वाले डॉक्टर एवं नर्स के पास विशेषज्ञता का अभाव।

④ अर्थोपचारिता

- 1) अर्थोपचारिता मितिक पर गर्भपात करवाया।

उपचारात्मक उपाय① ASHA की भूमिका

1) प्रशिक्षित बिघा जाना चाहिए एवं प्रांतीय स्तर पर उनकी क्षमता सशक्त होनी चाहिए।

② प्राथमिक स्वास्थ्य की बेहतर दशा

1) एनीमिया, खाद्य कपूरसम शक्ति से मुक्ति।

③ कमलान भारत - इसका लाभ व इसकी जानकारी सभी तक हो।

↳ (कार्वमोनिक स्वास्थ्य क्लोन उदाहरण है)

④ लक्ष्मी प्रयास

↳ मातृत्व लाभ आवेदनिका
पोषण कनिष्ठान
मातृ वंशना योजना

↓
इसका लाभ मिले।

संविधान के कडेटेड 42-वें समत
विकास लक्ष्य-5 को सुनिश्चित करने हेतु
मातृ स्वास्थ्य आवश्यक है। देविका विस्वास
क्योंकि मातृ संघ में प्रजनन के अधिकार
को मूल अधिकार माना गया है।

8. डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल भारत में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और उसकी बहनीयता से संबंधित स्थायी मुद्दों का समाधान करने में सक्षम है। इस संदर्भ में, देश को 'डिजिटल स्वास्थ्य' क्रांति के मुहाने पर लाने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Digital healthcare has the potential to address the perennial issues pertaining to accessibility and affordability of healthcare in India. In this context, discuss the role of Ayushman Bharat Digital Mission in putting the country at the cusp of a 'digital health' revolution. (Answer in 150 words) 10

डिजिटल स्वास्थ्य के द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जा सकती है। राज्य का यह दायित्व है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो (अनुच्छेद 39(e), 41 एवं 47 में)

डिजिटल स्वास्थ्य → वैशालेस स्वास्थ्य सुविधा
→ सभी को स्वास्थ्य सुविधा
↓
बहुधा मुक्ति मोर्चा कमान
भारत संघ (1944) → स्वास्थ्य का
वैशालेस अनुच्छेद 21 में निहित है
→ भौगोलिक विभाजन में सभी
↳ ग्रामीण एवं शहरी में (80% शहरी
शहरी क्षेत्र में)
कोयलाना भारत डिजिटल मिशन

① शेवर्स (चनात्मक सुधार - अस्पतालों की
स्थिति में सुधार

② भौगोलिक असमानता में कमी

पुडुच्चेरी में 1 लाख में 112 बिस्तर
जबकि बिहार में मात्र 7 बिस्तर हैं।

③ मानव संसाधन कमी में छुटकारा

डॉक्टर - 0.74/1000, नर्स - 7.7/1000
नर्स - 1.94/1000, WHO - 1/400

④ OOPEx में कमी

वर्तमान में OOPEx - 67%.

इसके कारण 55 प्रतिशत लोग
गरीब हुए हैं (शार्पिक सर्वेक्षण)

⑤ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर 15 का
व्यय 10 गुना प्रसिद्ध होगा है।

समान्यता डिजिटल विभाजन - इंफ़ोनेट

डिजिटल जागरूकता ग्रामीण - 31%
शहरी - 77%

डिजिटल IT उद्योगी की कमी

कारग्रेडि
ताह

संविधान के कर्तव्यों के
पालन हेतु स्वास्थ्य का बर्बाद
प्रदान करना

सबत विकास लक्ष्य - 3 का उद्देश्य

जनसांख्यिकी लक्ष्यों एवं मानवीय

वर्गी के विकास हेतु सार्वभौमिक स्वास्थ्य स्थापना है।

9. दक्षिण एशिया से एकमात्र G20 सदस्य के रूप में, भारत के लिए G20 का नेतृत्व वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया की आवाज को बुलंद करने के लिए एक प्रभावी मंच के तौर पर इस समूह का उपयोग करने हेतु एक आदर्श अवसर है। टिप्पणी कीजिए।

As the only G20 member from South Asia, the G20 leadership is an ideal opportunity for India to use it as an effective platform to amplify South Asia's voice at the global stage. Comment. (Answer in 150 words) 10

G20 की वर्तमान दृष्टिकोण भारत के
पालन है। ऐसे में भारत दक्षिण
एशिया के हितों को बढ़ावा देने
इस मंच की समावेशिता बढ़ा
सकता है।

भारत के द्वारा इस मंच के उपयोग
के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए

- ① हिंदू आवाज मंच - चुला, मुम्बई,
निपट लाधारित एवं समावेशी हिंदू
अतिथि बनाना चाहिए।

- ② दक्षिण एशिया - यहाँ विकास
विकास एवं क्षेत्रीय को
बढ़ावा देने के लिए अंतराष्ट्रीय
सहयोग।

② बायीं, भुवने, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु

④ पर्यावरणीय समस्या जलवायु परिवर्तन के कारण यह क्षेत्र त्वरित पुनर्निर्माण है। ऐसे में क्लाइमेट लक्ष्य का ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

⑤ शांति पुनर्निर्माण करना - अफगानिस्तान, म्यांमार में कबालि-रा समाधान करना।

⑥ आर्थिक दुहा - नेपाल, श्रीलंका बांग्लादेश आर्थिक तंगी से तटस्थ हैं। विश्व लक्ष्य से मदद की खोज जारी चाहिए।

भारत के पास बहुत प्रयोग करने की क्षमता है।

10. भारत-यू.ए.ई. CEPA दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तथा भारत को इस क्षेत्र में व्यापक पहुंच प्रदान करेगा। चर्चा कीजिए।
The India-UAE CEPA will serve as a catalyst to bolster economic ties between the two countries and give India greater access to the region.
Discuss. (Answer in 150 words) 10

विगत कुछ वर्षों में भारत-उ.अ.ई.
के संबंधों में व्यापक सुधार हुआ है।
CEPA हो या ILU का विकास:
उनके फलपक्ष उद्घाटन है।

आर्थिक संबंधों की मजबूती - (CEPA द्वारा)

- 1) आर्थिक संबंधों में दोनों देशों में
व्यापार में तीव्र वृद्धि होगी।
- 2) राष्ट्रों के द्वारा अवसंरचनात्मक विकास
में सहयोग होगा।
- 3) ये राष्ट्र मिलकर अन्य राष्ट्रों के भी
निवेश करेंगे।
- 4) भारत को ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति
पुनिश्चित हो सकेगी।
- 5) रुपये की कीमत 0.84 में लाया होना
सत्य हो जाएगा है।
- 6) केन्द्रीय बैंक में भी सहयोग बढ़ेगा।

ह्पापक पहुंच

- ① भारत की UAE के ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच
- ② Brand India - के तहत भारतीय संस्थानों का UAE में कंपस जुड़ना
L IIT Delhi का
- ③ UAE के माध्यम से अन्य गल्फ देशों के साथ संबंधों में सुदृढ़ता
- ④ मल्टी होर्जुन जलसम्पत्तियों में सुलभा प्राप्त करना
- ⑤ रक्षा क्षेत्र में सहयोग
भारत CSPA दोनों देशों के संबंधों में गिन का पल्लव सक्षित होगा।

11. एक दोषपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली, सुविचारित कानून की अनुपस्थिति और डोमेन विशेषज्ञता की कमी को भारतीय न्यायपालिका के लिए नई चुनौतियों के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा कीजिए।
A dysfunctional criminal justice system, absence of well-considered legislation and need for domain expertise, are being seen as the new challenges for the Indian judiciary. Discuss. (Answer in 250 words) 15

भारतीय न्यायपालिका में 'हार्ड डायल' केंद्रित
सी संख्या 77% हो चुकी है एवं 'लेषमिहि
फर' 47% है। इसका मुख्य कारण उपर्युक्त
चुनौतियाँ हैं - सुविचारित कानून की अनुपस्थिति,
डोमेन विशेषज्ञता की कमी, दोषपूर्ण आपराधिक
न्याय प्रणाली।

भारतीय न्यायपालिका के निम्न चुनौतियाँ

① दोषपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली

② न्याय की जाँच न हो पाना

↳ लेषमिहि फर - 47% (विधि
आयोग)

③ जाँच करने वाली व कानून लागू
करने वाली संस्था एक ही है

④ जाँच करने में पुरानी व्यवस्था का
लाभ देना - 2PC 1860
CrPC - 1973

4) जॉय छवि में शामिल लोगों का
अभिज्ञान नहीं।

पुविचासि कासुन की मनुष्यसिचि

4) POCSO Act - 16-18 वर्ष में

लैंगिक संबंध प्काग कपराद्य

46.6% मामले रानी उम्र के हैं।

4) स्वविवेकाधीनार - कनेक मामलों में

जैले - राजप्रेह नासुन (1961 प्कम)

4) परिभाषा का अभाव - पादालप की

अवधानना परिभाषित नहीं है

4) कासुनों का अभाव - हेर स्पीच

कालिष्ठ, हिरासत में हिरा के

लिष्ठ, माँव लिचिंग कालिष्ठ

डोमेन विशेष्कता का अभाव

① आधीनारों के मामले में

4 ऐसे व्यसिचों की

मिउसि, जिह विशेष्कता नहीं है

② तस्तीक की जानारी का अभाव

③ नार्क टेस्ट, DNA विश्लेषण
कास्टि का जॉच न होना।

④ तनव्यता - पुलिस, डॉक्टर एवं
-आपातकर्मियों में-

डुसाव → Dr. वसु वाड के आपातकर्मियों
सिस्टम के हिस्सा में राज्य स
परोक्ष योगदार बनाया
→ कतः इति काइन
काना चाबि

→ कानों का नवीनीकरण
→ कंपाउंड बिनाप
पब्लिश - 2022

→ मोडल जेल कविनिष्ठा - 2022
में व्याप्त करना

→ गुजरा सभितिकी सिद्धांतियों
में लागू करना

कतः नवीनीकरण ही प्रासंगिक
कानून का आधार है।

12. दल-बदल विरोधी कानून भारत में राजनीतिक अस्थिरता के मुद्दे को किस हद तक हल करने में सक्षम रहा है? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए।

To what extent has the anti-defection law been able to address the issue of political instability in India? Discuss with suitable arguments. (Answer in 250 words)

15

इसके संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा राजनीतिक दलित्वा एवं अस्थिरता को तोड़ने के लिए संविधान में अनुच्छेद-10 जोड़ा गया था जिससे 'भाषा राग-गया राग' की समस्या दूरबाधी जा सके।

दल बदल कानून की प्रासंगिकता

- ① राजनीतिक दल के सदस्य को व्हिप के अनुरूप कार्य करना होता है।
- ② दल की सदस्यता से त्यागपत्र देने पर असदस्य की सदस्यता रद्द हो जाती है।
- ③ दल-बदल कानून के संदर्भ-पापालप हस्तक्षेप का लक्ष्य है
↳ किसी भी होनहार काम को चिन्तित वाद
- ④ जनताकांक्षा को महत्व देना व राजनीति में छरीद प्रत्येक में रूनी लाना

समस्या है

- ① अवधन / समापति द्वारा पक्षपात
 - 1) निर्णय इसी के द्वारा लिया जाता है।
 - 2) मविपुल विधानसभा ने 3 वर्ष तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।
- ② वैरक्षापूर्वक त्याग की व्याख्या नहीं
 - 1) वैरक्षापूर्वक लड़ाकू त्यागना की व्याख्या न होने के कारण दुर्कल्पों हो रहे हैं।
- ③ अनुच्छेद 105 एवं 194 का उल्लंघन
 - 1) सदन जनसमिति की कार्य दल समिति होते जा रहे हैं।
- ④ ठानी की सीत नहीं - हाल ही में शुद्धाराध, मनील एवं मध्यप्रदेश में सेली धरना दली है।
- ⑤ समय सीमा का उल्लेख नहीं
 - 1) दल दल पर निर्णय लेने के लिए निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं है।
- ⑥ वाकें संविधान संशोधन - यडि 2/3 सदन दल
बनाने तो वह इस कानून के नहीं शास्त्रा

सिफारिशे

- 1) उच्चतम न्यायालय ने अध्यक्ष/सभापति के कार्य को स्वतंत्र प्राधिकरण से झिल्लेस करने की बात की।
- 2) 2nd ARC ने कहता है तो मामलों पर निर्णय निवाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल/राष्ट्रपति लें।
- 3) वीरान गेहचन्द्र सिंह बनाम अध्यक्ष गणिपुर विधानसभा
 - निर्णय के लिए सख्त लीमा ना इन्फ्लेज
- 4) किहोतो होलोहन वाड
 - वन कठिनी की -पाधिक समीक्षा हो सकी है।

होस्त की जीवन्ता बनास
स्थने हेतु अधिर सदन एवं
सारगार्भिक संवाद को बढ़ाया जाना
चाहिए ।

13. भारत में अंतर्राज्यीय नदियों का प्रबंधन परस्पर विरोधी संघवाद के कारण विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। चर्चा कीजिए। साथ ही, उन तंत्रों को रेखांकित कीजिए जिनका उपयोग भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए किया जा सकता है।

Governance of inter-state rivers in India suffers from various issues due to conflictual federalism. Discuss. Also, highlight the mechanisms, which can be utilised to resolve inter-state river water disputes in India. (Answer in 250 words) 15

संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों के प्रबंधन का उल्लेख है जिससे अंतर्राज्यीय जल विवाद की समस्या को संवाद के स्तर पर सुलझाया जा सके एवं संघवाद की प्रवृत्ति मजबूत हो सके।

निहित समस्याएँ

- ① जल राज्य सूची का विषय है जबकि अंतर्राज्यीय जल संघ सूची का विषय है
- ② राजनीतिक हवालावाद
राजनीतिक ग्लों के द्वारा वोटबैंक की राजनीति के लिए समस्या-समाधान नहीं किया जाता है।
- ③ संवैधानिक तंत्र की विफलता
अनुच्छेद 262 एवं 263 के तहत स्थापित निकायों का प्रभावी न होना।
- ④ स्पष्ट विभाजन नहीं अंतर्राज्यीय नदी के जलों का स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ है।

(5) जल पर निर्भरता

- १) कृषि मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर है।
- २) जल शक्ति के द्वारा किती उत्पादन
- ३) मत्स्यन उत्पादन आदि।

उपलब्ध तथ्य① कृच्छ्रेय 262 - इसके तहत

- १) नदी बोर्ड अधिनियम 1956 (2019 में संशोधित)
- २) बांध सुरक्षा अधिनियम - 2019
- ३) अन्तर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 2019 में संशोधित)

↓ इसके अन्तर्गत

- 4) अधिनियम 1 वर्ष के अन्दर जल बँकरो का समाधान करेंगे (6 महीने की कालिम्स समय)
- १) फिर DRC के तहत समाधान होगा। (2 वर्ष एवं 1 वर्ष का कालिम्स समय)

② कृच्छ्रेय - 263 - अन्तर्राष्ट्रीय

परिषद के द्वारा समस्या समाधान के लिए मंच प्रदान करना।

③ क्षेत्रीय परिषदें, त्रिनि दापोग एवं
राष्ट्रीय विकास परिषद
संघवाद की गतिशील
के लिए बाल संघ प्रदान करना।

निष्कर्ष NCRC के अनुसार
अन्तर्राष्ट्रीय जल विकास के निपटान के
लिए व्यापक एवं प्रभावी कानून की
आवश्यकता है।

उत्तर: समन्वय, सहयोग एवं
राष्ट्रियता के द्वारा प्रभावी एवं संस्थागत
मॉडल के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जल
विवाद का निपटारा किया जाना चाहिए

14. उत्तर-औपनिवेशिक दस्तावेज होने के बावजूद भारतीय संविधान के उन मूलभूत पहलुओं का सविस्तार वर्णन कीजिए, जिनके संदर्भ में यह अपने समकालीन संविधानों से भिन्न था।

Elaborate on the fundamental aspects in which the Indian Constitution differed from its contemporaries despite being a post-colonial document.
(Answer in 250 words)

15

भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से
विरहित है। यह स्रोत बाह्य एवं
आंतरिक हैं।

→ बाह्य स्रोत - USA, UK, ऑस्ट्रेलिया
फ्रांस आदि।

→ आंतरिक स्रोत - सांस्कृतिक इतिहास
सांसाजिक इतिहास
आर्थिक इतिहास
स्वतंत्रता आंदोलन से
प्रेरित

उत्तर-औपनिवेशिक दस्तावेज के रूप में

① संसदीय लोकतंत्र

यह व्यवस्था ब्रिटेन से प्रेरित था

② 1935 का भारत अधिनियम

→ संविधान के अधिकांश प्रावधान
1935 से लिए गए थे।

3) IPC की व्यवस्था 1860 वाली थी थी।

④ -घाफलीन तंत्र 1937 में स्थापित
तंत्र के कुरूप था।

समकालीन संविधानों से भिन्नता

① सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित

4) बहुधैव कुरूपकम - संविधान की
तत्त्वावगा - बंधुत्व का भाव

4) नव्यवेदांत दर्शन - पदाविरा संरक्षण
के प्रावधान (अनुच्छेद 48A, 51A(8))

4) सहिष्णुता - अकबर के दीन ए-इलाही
एवं अशोक की धम्म नीति के अनुसार

4) बहुलभावादी संस्कृति - लोमैकम विम्रा
बहुधा वदन्ति (अनुच्छेद 29, 30)

② स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा प्रेरित

4) अनुच्छेद 23 एवं 24 के प्रावधान इतने
ही प्रेरित थे।

4) सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का
प्रावधान।

4) समाजिक पक्षपात की भवधाना

③ सामाजिक मूल्यों पर आधारित

नीति निर्देशक तत्व को बाध्यकारी नहीं
क्या गया, उल्टे सभी मूल्य फिर बार
जितने राज्य का वैश्व दायित्व प्रतिबिम्बित है।

④ रचनात्मकता

१) लोकतंत्र के रूप में

↳ राजशाही व्यवस्था के स्थान
पर गणतंत्र का चुनाव।

२) अनुच्छेद 32 एवं 226 का प्रावधान।

३) अनुच्छेद 5 एवं 6 के तहत जनजातीय
पम्परा का सम्मान।

इतना संविधान बना है सर्वोच्च
पुस्तक के रूप में भारतीय संविधान
का निर्माण किया जिस कारण है
भारतीय लोकतंत्र आज भी मजबूत एवं
सुदृढ़ हो रही है।

15. मुफ्त उपहार, विशेष रूप से चुनावों से पहले, समाज के लिए लाभकारी होने की बजाय अधिक हानिकारक हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में युक्तिसंगत तर्क दीजिए।
Freebies, especially ahead of elections, do more harm than good to the society. Do you agree? Give logical arguments in support of your answer.
(Answer in 250 words) 15

मुफ्त उपहार से व्यापक राजनीतिक
दलों के द्वारा चुनाव के दौरान
वोटों के रूप में निशुल्क उपहारों की
पेशकश है।

हाल ही में उत्तम व्यापार ने
वार्चिक कल्याण एवं राज्य के वित्तीय
स्वास्थ्य में संतुलन बनाने का निर्देश
दिया है

मुफ्त उपहार - वित्तिकारक

① वार्चिक मुद्दे - राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य
पर प्रभाव
- तेलंगाणा के द्वारा कुल राज्य का
का 35% एवं राजस्व का 63%
मुफ्त उपहार पर व्यय।

② राजनीतिक मुद्दे - अनुच्छेद 14 के तहत
राजनीतिक दलों के समानता की भावना कम हो

होती हैं

- 3) पर्यावर्णीय स्थिति - उर्वरक पर साक्षिणी
के कारण मृदा एवं जल प्रदूषण।
→ जल के उपयोग पर झूट के कारण
अल्पदिन जल स्रोत को बढ़ावा।

- 4) तामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तानाशा

* बेरोजगारी कता मिलने से अनुरक्षणता
को बढ़ावा मिलता है।

- 5) अवसंचनात्मक मुद्दे - सड़क, रेलवे,
विजली आदि अवसंचनात्मक विकास पर
सरकार का कम ध्यान रहता है।

लाभ

- 1) DRDP में राज्य के वैश्विक दायित्व
दिखाए गए हैं।

↳ मुख्य उपहार डीपी के अनुक्रम

- 2) निर्धनता एवं बेरोजगारी पर आकाशिक
रोक लगाती है।

↳ मोर्चा-19 में मुख्यतः के
मुख्यमंत्री एवं निर्धनता से करोड़ों लोगों को बचाव है।

③ महिला सक्षमता - महिलाओं के लिए स्कूल, लैपटॉप चाडि उन्हें सक्षम करने के लिए आवश्यक है

4- स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी दुआ

न्यायिक निर्णय

1) सुश्रमणम कानूनी कानून समित्यरूप (2011)

↳ न्यायालय ने निर्णय दिया कि निर्वाचन आयोग के राजनीतिक दलों के साथ मिलकर वस संबंध में द्विआनिर्देश तैयार करना चाहिए।

निर्वाचन आयोग की हाइब्रिड आचार संहिता 2016 की भाग VII में नए इलेक्शन की है।

निष्कर्ष : राजनीतिक दलों को मुख्य उपहार, राज्य के विनीय स्वास्थ्य एवं अवसंरचनात्मक क्रिया में संलग्न करने की आवश्यकता है।

16. भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने के लिए शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए हैं। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस मिशन को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

The Smart Cities Mission, which was launched to change the urban landscape of India has produced mixed results. Discuss. Also, highlight the challenges faced in executing the Mission. (Answer in 250 words) 15

स्मार्ट सिटीज मिशन के द्वारा शहरों में आधुनिकीकरण, परिवहन, सिंचाई एवं हस्त प्रयाण इत्यादि की संरचना की जाती है। हालांकि इसके मिश्रित परिणाम मिले हैं —

समाचारिक परिवर्तन

① सभी के लिए आवास

आवास की संरचना लुप्त होती है।
फलतः बेघर लोगों की संख्या में भी बढ़ाव है।

② परिवहन

CNG आवाहन, ई-परिवहन एवं मेट्रो का तेजी से विकास।

③ बिजली की सुविधा

सभी शहरों में 24x7 बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

④ पेपजल - तल के द्वारा सनी की बूझ
पेपजल की छुविहा मिल रही है।

⑤ खट्टना - अपशिष्ट प्रबंधन की उत्तम
पद्धति उपलब्ध है।

चिंगाई

① मलीन वस्तुओं की बढ़ती संख्या

→ भारत में मलीन वस्तुओं की संख्या में
तेजी से वृद्धि हो रही है।

② शहरी बाढ़ - हाल ही दिवसों में वर्षा
से शहर जलमग्न हो गया।

③ शहरी उष्मा द्वीप - शहर के तापमान
में निरंतर वृद्धि हो रही है।

④ पर्यावरण प्रदूषण - ध्वान, वायु एवं
जलप्रदूषण की तीव्रता बढ़ी है।

⑤ परिवहन में जाग की समस्या
→ दैनिकिक वाहन

⑥ नोर्वेनार्मि समस्याएँ - कचरा, कालव्युत्स,
लकड़ीपत्र में वृद्धि

मिश्रण को लागू करने में ठोस चाली-युक्तियाँ

① वित्तीय समस्या, स्मार्ट सिटी के लिए
कम पिन राबंटन
कॉन्सिडर पिन का कुशल दोहन नहीं

② कृषी जनसंख्या
प्रदेशों में बढ़ता प्रवास।
उपश्रुम्ह रुचि का अभाव।

③ पर्यावरणीय चुनौतियाँ → वनों के ह्रास
से पर्यावरणीय चुनौतियाँ बढ़ी हैं।

④ अपशिष्ट प्रबंधन → विभिन्न प्रकार के
अपशिष्टों का कुशल प्रबंधन नहीं

⑤ मानव संसाधन की कमी - जॉन्स एवं
शोध के लिए मानव संसाधन की कमी

समस्त विकास लक्ष्य -11 के
अनुसूच साहते के विकास हेतु स्मार्ट
गाँव, सन्नी के लिए आवास एवं जनजीवन
मिश्रण काडि को प्रभावी रूप से
क्रियान्वीत किया जाना चाहिए।

17. यह तर्क दिया गया है कि भारत में उद्यमिता परिवेश के समक्ष विद्यमान विभिन्न बाधाओं के बावजूद, भारत के भविष्य को इसके उद्यमियों द्वारा आकार दिए जाने की संभावना है। टिप्पणी कीजिए।
It has been argued that despite several hurdles faced by the entrepreneurship ecosystem in India, the future of India is likely to be shaped by its entrepreneurs. Comment. (Answer in 250 words) 15

वर्तमान समय में भारत का जनसांख्यिकी
लाभांश हमारे पक्ष में है। ऐसे में
3D (Demand, Demography, Democracy) के
कटुफल होने के कारण भविष्य
इज्जत दिवस के रहा है।

उद्यमिता परिवेश के समक्ष बाधाएँ

① कृषक जनसंख्या - नीति आयोग के
अनुसार प्रति वर्ष 30 लाख ^{नए} स्नातक में
से 3 लाख ही कृषक शिक्षा लेना विवक्षित है।

② किरीय समस्या - भारत में उद्यम के लिए
भूतल प्राप्त करना बहुत मुश्किल है।

③ बुनियादी ढांचात्मक समस्या - सड़क, रेलवे,
विजली, जल की सुविधाएँ सभी क्षेत्रों
में समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

④ निजी क्षेत्र में बाण
हाल ही में साचन
ने 75% बाण उदान किया।

⑤ इन कोड्स इंग बिजनेस
कंपनी के लिए पंजीकरण करना कठिन,
अत्यचार जैसी समस्याओं ना होना

संभावनाएँ

① हाल ही में GDP इंहिदर 7% पहुंच
गयी है
मांग को बढ़ावा मिलेगा।

② जनसंख्या लाभांश भारत में
सोसा बापु 28 वर्क है।

2045 तक हमारे पक्ष में होने
का अनुमान।

③ चीन का विकल्प चीन से कोविड ने
दोस्त बनना कारोबार खत्म करने वाली
कंपनी भारत में निवेश कर रही है।

④ सकारि ज्यास कोशल के लिए
कोशल एवं उद्योग
मंत्रालय, STRIVE, IMPRES बापि

५) राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के
अनुसार लक्ष्य के साथ पढ़ना
(उत्पादक)

⑤ युवा महिला कार्यक्रम - मिनिसे के

अनुसार महिलाओं के कार्यक्रम में
शामिल होने पर GDP में इन्क्रिमेंट
1.4% की दर से बढ़ी होगी।

⑥ सामाजिक तंत्रों पर ध्यान

सकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य,
स्वच्छता पर विशेष ध्यान

मतः सबका साथ, सबका विकास
सबका प्रवास, सबका विश्वास की
संकल्पना से भारत के उज्ज्वल
भविष्य की कल्पना की जा रही है।

18. हालांकि, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना ने लैंगिक भेदभाव पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन यह खराब कार्यान्वयन और निगरानी के कारण वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही है। चर्चा कीजिए।

Though the 'Beti Bachao, Beti Padhao' scheme has given much-needed attention to gender discrimination, it has failed to yield desired results due to poor implementation and monitoring. Discuss. (Answer in 250 words) 15

भारतीय सरकारों की मुख्य समस्या
'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' है जिसके कारण
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों
में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई है।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के परिणाम

स्कारालोक

- 4) संभावित प्रसव को बढ़ावा मिला है
↳ 88% कुद सन्धों में 95% है।
शून्य हल्पा में नमी काफी है।
- 4) नामांकन दर में वृद्धि
↳ वरिष्ठों के नामांकन दर
में स्त्रियों में वृद्धि हुई है।
- 4) उच्च शिक्षा (एचएम) में महिलाओं
की भागीदारी बढ़ी है।

STEM $\nearrow$ भारत - 40%
में भागीदारी, विश्व - 35%

4) स्कूलों में गणित के कारण एनीमिया
में कमी, पोषण में उद्धा

परमिट डे मिल योजना के तहत
4) जागरूकता के लिए वेबिनारों के
जोड़ जागरूकता बढ़ी है।

चुनौतियाँ

① बिना का दोहन नहीं - इतनी बावलि
बिना का 70% ही उपयोग में लाया
जा रहा है।

② मानव संसाधन में कमी - इचित निगामी
एवं निरंतर देखभाल के लिए अभिलेख
मानव शक्ति का बभाव है।

③ दृढ़ वृद्धावस्था के सकार एवं राज्य
सकारों के मध्य समन्वय का कभाव

↳ राज्य सकारों द्वारा कन्य
योजना चलायी जा रही है।

④ जागरूकता → स्मूथिंग फ़ार डाल तो
दुनिश्चित हुआ है किन्तु स्मूथिंग फ़ार
डाल नहीं ।

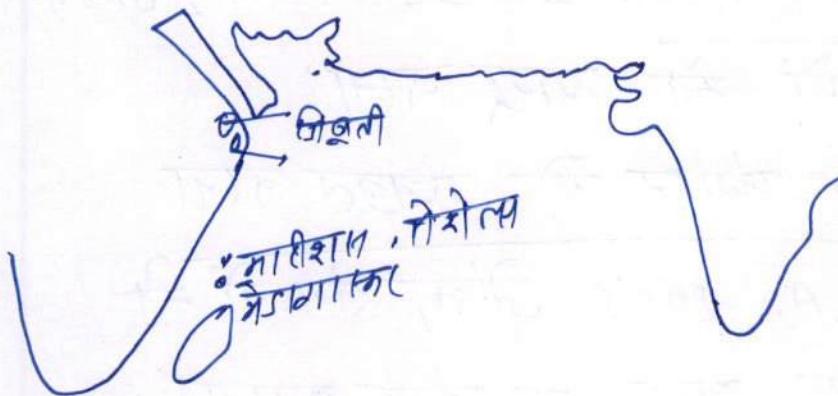
⑤ ड्राप आउट रेट प्राथमिक शिक्षा
के बाद लड़कियों में ड्राप आउट
रेट अत्यधिक है।

सुझाव → परदशी तरीके से धन आवंटन
→ NCO सिविल सोसायटी के
द्वारा निर्मात्री
→ निम्न निर्मात्री के लिए जल्द
5 वर्ष में कगरी का गठन
→ सावधि धन का कुशन दोहन
भारत को 5 डिजिटल इंडिया
की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक, शैक्षणिक
एवं राजनीतिक आधार स्थापित करने हेतु
सामाजिक आधार दुनिश्चित करना
आवश्यक है।

19. दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में सुरक्षा खतरों के स्वरूप और उनकी बारंबारता में वृद्धि के मद्देनजर, इस क्षेत्र में लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के संबंध में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा कीजिए।

As security threats increase in form and frequency in the South-West Indian Ocean, discuss the role played by India in relation to small island developing states (SIDS) in the region. (Answer in 250 words) 15

दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर के सुरक्षा के प्रमुख कारणों में स्थिती उत्पत्ती, ब्रह्मण जैसी समताप है।



बारंबारता में वृद्धि के कारण

- ① गरीबी - इस क्षेत्र में व्याप्त गरीबी है जिसके कारण
- ② भूकंप - ग्लोबल हंगर रजिस्टर में ये दक्षिण पायदान पर हैं।
- ③ वैश्विक तंत्र का प्रभाव न होना - यहाँ पर वैश्विक गवर्नेंस स्थापित नहीं है।

- ④ महत्वपूर्ण व्यापारिक गति लम्बी डूबती
का मुख्य कारण यहाँ का महत्व है
↳ व्यापार के लिए देश बकी
गति का चुनाव करते हैं।

वास्तविक श्रमिका

- ① मलेशिया सहयोग - LC कन्वेंशन जैसी
साधनों को लाया गया।
- ② क्षेत्रीय संगठन को मजबूत बना
20RA, 20NS जैसी संगठनों को
सकारात्मक वाड का गंव बनाया।
- ③ सहयोग - भारत मॉरीशस, सेशेल्स
जैसे देशों के कार्मिक विकास
को लिए पण्डित विनीय मदद कर रहा है
- ④ विकास-आत्मक निर्माण - इन देशों में
विकास-आत्मक विकास के लिए भारतीय
पलों को मजबूत कर रहा है।

⑤ AAEC का निर्माण - Asia Africa
Growth Corridor

↳ भारत - जापान की सहपता के
कनेक्टिविटी की सुदृष्टिकोण के निर्माण

यूरोपियाँ → चीनी मार्ग
→ पर्यावरणीय समस्या एवं
जलवायु परिवर्तन
→ क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ

कारण: लघु द्वीपीय देशों के सहज
भारत के सक्रिय सहभागिता
(इन्फ्रास्ट्रक्चर की है जिससे यहाँ का
विकास एवं आर्थीय स्थिति सुदृष्टिकोण
हो सके।

20. चूंकि भारत अपने पड़ोस की पुनः कल्पना कर रहा है, इसलिए उप-क्षेत्रों के माध्यम से सीमा-पार कनेक्टिविटी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। विश्लेषण कीजिए।
As India re-imagines its neighbourhood, cross-border connectivity through sub-regions is becoming increasingly vital. Analyse. (Answer in 250 words) 15

विकास का वर्तमान साधन कनेक्टिविटी है जो क्षेत्र जिसका अधिक कनेक्टेड है, उनके विकास की संभावना इसी अधिक है। [उदाहरण]

- ① EU के विकास की गति तीव्र है क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है।
- ② दक्षिण एशिया में बारीब, बुलबुली, कम व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य कारण इसकी कमजोर कनेक्टिविटी है।

[भारत के लिए महत्व]

- ① भारत-नेपाल संबंधों में
 ५ नोरीहारी - अमनेज्जंग धारपल्लन का निर्माण
 रेलवे एवं सड़क के द्वारा जोड़ना
 जिससे व्यापारिक एवं सामाजिक संबंध सुदृढ़ हो सकें।

- ② ईरान का चाबहार - भारत मध्य एशिया तक पहुँच बनाने के लिए ही चाबहार बन्दरगाह का विकास किया
- ③ मध्य एशिया तक पहुँच देना
↳ TAPI, IPI परियोजना पर कार्य चल रहा है जिससे क्षेत्रीय कोसिक्सी बढ़ सके
- ④ एस ईएन पालिसी के तहत
↳ IMA परियोजना, गंगा-झांग सहयोग
↳ भारत का पूर्व एशिया से जुड़ाव
- ⑤ एनू डॉट नेटवर्क का समर्थन
↳ हिंद फ्रेशांतर में स्वतंत्रता निर्माण देना
- ⑥ भारत-बंगलादेश - रेलवे, सड़क एवं
↳ जलमार्ग का विकास
↳ हल्दीबाड़ी-बिन्दारी से रेल संपर्क से जोड़ना

पुरे तिया

क्षेत्र में बाकिस्तान की
निष्पत्ति

चीन का BRI प्रोग्राम

BRI व प्रोग्राम में भारत की
अनिका भाग

नेहरूवादी फार्म पालिसी एवं
उत्तराल की जॉइन्ट पॉलिसी से
पह बुनियादी ढांचे गजब हो
सकती है